है कि इसके लिए 10 दिन की ट्रेनिंग होती है उसे किस तरह से बनाना है किस तरह से लगाना है क्या करना है। यह लोग दूसरों को ट्रेनिंग देंगे इसके लिए तो इनको थोड़ी ज्यादा ट्रेनिंग चाहिये लेकिन यह सब के लिए लागू नहीं है । शायद हमारे मित्र यदि इसकी ट्रेनिंग लेना चाहें तो एक दिन में ही उनका पूरा चूल्हे का ज्ञान हो जाएगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Deshmukh.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Madam, considering the vast backwardness in the country, have any efforts been made to introduce this scheme in the backward areas and the Scheduled Tribe areas and, if any efforts have been made, what is the extent to which efforts have been made?

SHRI VASANT SATHE: Actually, Madam, the main thrust is on the backwardness and we are giving special subsidy as far as the Scheduled Tribe areas are concerned. The element of subsidy for protable chulhas for all the areas in the country, is 50 per cent. But, as far as the Scheduled Caste and Scheduled Tribes and hilly areas are concerned, it is 75 per cent and we are making a special effort and as far as the remote areas like Sikkim are concerned and as far as the hill areas, desert areas, etc. are concerned. So, this programme has a definite emphasis on the weaker sections and the tribal areas.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Next Question. Question No. 384.

*384. [*The questioners (Dr. Shyam Sunder Mohapatra and Shri V. Gopalsamy) were absent for answer,* vide *col.* 29-30 infra.]

*385. [*The questioner (Shri M. Basavaraju) was absent. For answer, vide col.* 30 infra.]

THE DEPUTY CHAIRMAN : Question N. 386. Mr. Vikal.

गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना

***386. श्री राम चन्द्र विकल : †**
श्री आदिनारायण रेड्डी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोबर गैस संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के दौरान इस प्रकार की योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1984-85 के दौरान गोबर गैस संयंत्र लगाने के निर्धारित लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त कर लिया गया है तथा 1985-86 के वर्ष के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां ।

(ख) सातवीं योजना की अवधि के दौरान, बायोगैस विकास के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना मजबूती से चलायी जा रही है । यह परियोजना तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवा सुविधाएं, मरम्मत और रख-रखाव मानीटरन एवं मूल्यांकन, केन्द्रीय आर्थिक सहायता टनकी जाव फी, इत्यादि प्रदान करती है । एक अलग योजना के अंतर्गत, सामुदायिक एवं संस्थागत बायोगैस संयंत्रों का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

(ग) वर्ष 1984-85 के लिए 1.50 लाख संयंत्रों के लक्ष्य की तुलना में, 1.80 लाख संयंत्र स्थापित किए गए थे जोकि लक्ष्य से 20 प्रतिशत अधिक

†सभा में यह प्रश्न श्री रामचन्द्र विकल द्वारा पूछा गया ।

थे तथा 1983–84 में स्थापित किए गए संयंत्रों की अपेक्षा 95 प्रतिशत अधिक थे। वर्ष 1985–86 के लिए 1.50 लाख संयंत्रों का लक्ष्य था जिसको 1.8 लाख संयंत्र तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

श्री राम चन्द्र विकल : श्रीमन, सातवीं योजना में इसको मजबूती से चालू करने के लिए जो मामला विचाराधीन है, उसमें विशेष योजनाएं क्या हैं और उनके लिए आर्थिक साधन जुटाने के लिए आपने क्या रूपरेखा बनाई है। साथ ही एक अन्यत्र योजना भी बताई गयी है, उसकी रूपरेखा भी बताएं और उस पर होने वाला संबंधित व्यय जो सातवीं योजना में चाहते हैं उस पर भी प्रकाश डालें?

श्री वसन्त साठे : अभी अगले साल में हम सोच रहे हैं कि 1.80 लाख लगायें। इसी तरह से इसको बढ़ाते रहें। लेकिन यह सब कुछ अवलंबित होगा, कितने हमें रिसोर्सेज इसके लिए मिलते हैं। यह है जरूरी। इस पर सेवेन्थ फाइव इयर प्लान में 15 लाख का टारगेट हमने रखा था। उसके लिए 177 करोड़ लगेंगे ऐसा सोचा गया था। लेकिन बहुत कुछ इस पर अवलंबित होगा कि सातवीं योजना में एक्चुअली हमें कितना मिलेगा क्योंकि जनरल रिसोर्सेज आप जानते हैं देश में, तो उसकी जो कठिनाई है उसकी वजह से काफी कटौती इसमें होने वाली है या होगी। लेकिन और कहीं से रिसोर्सेज यदि जुटा सकें, लोग खुद इसमें आ सकें तो देखेंगे। जरूरत तो है। ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे।

श्री राम चन्द्र विकल : यह गोबर गैस की एक उपयोगी योजना है गांवों के किसानों के लिए और देश के आर्थिक विकास के लिए, इसलिए इसका जो प्रचार प्रसार है वह रेडियो टेलीविजन द्वारा हो या कोई ऐसे प्रचारक टेक्निकल, गांवों में जाकर, इसका प्रचार कर सकें तो आप इसके व्यापक प्रचार के लिए किन संसाधनों को जुटाना चाहते है ताकि इसकी उपयोगिता का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके और देश के आर्थिक विकास में यह सहयोगी बने?

श्री वसन्त साठे : जितने प्रचार के माध्यम है जैसे दूरदर्शन पर इसके काफी प्रोग्राम्स आये हैं आपने देखे होंगे। इसके अलावा हम हर राज्य में कुछ नोडल एजेंसीज मुकरर करते हैं जो इन बायो गैस को लगायें और उनको प्रति बायो गैस प्लांट पर 300 रुपये देते हैं एज ए इंसेंटिव। हमने देखा है कि यह काफी प्रभावशाली चीज हो रही है इसके अलावा यह सोचा जा रहा है कि गांव के स्तर पर ब्लाक के स्तर पर, जिले में भी जिसे कहते हैं, इन्टेग्रेटेड एनर्जी सेंटर्स, तो टोटल नान-कन्वेंशनल सोर्सेज आफ एनर्जी जो हैं जिसमें सोलर आयेगा, विंड मिल आयेगी, बायो गैस आयेगी, इम्प्रूव चूल्हा आयेगा, इन सारी योजनाओं को कार्यान्वित करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाये। इसका प्रयास कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : यह माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित है। मंत्री जी ने बताया कि सर्विस फैसिलिटीज रिपेयर्स मेन्टिनेंस आदि की सुविधाएं हैं। मेरी जानकारी के अनुसार जो सेटबैक इस योजना को लग रहा है, वह इनकी सर्विस फैसिलिटीज न होने के कारण है।

मेरे प्रश्न के तीन पार्टस हैं— पहला, क्या मंत्री जी इनके सर्विस, मैंटेनेंस आदि की ओर विशेष ध्यान देंगे?

दूसरा, जो उन्होंने उत्तर में बताया है कि सामुदायिक और संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल और कम्यूनिटी प्लांट्स एस्टेबलिश किये हैं, क्या वह बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस प्रकार के कितने इंस्टिट्यूशनल और कम्यूनिटी, जो आम जनता के लिए हैं, वह स्थापित कर चुके हैं? और

तीसरे, बिरला विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कालेज, गुजरात, वल्लभ विद्यानगर ने एक स्टडी की है और उस स्टडी के अनुसार, माननीया, जो यह हायसिंथ है, जिसको देहात में समुद्र सोख कहा जाता है, जो झीलों को, तालाबों को, नदियों को भी खराब करता है, सब पानी सोख लेता है, उससे गोबर के मुकाबले कहीं अधिक गैस तैयार होती है, तो क्या उसका भी कोई प्रयोग करके आगे इसमें और सुधार करने की इनकी कोई स्कीम है ?

श्री वसंत साठे : अवश्य है । यह देखा गया है कि ऐसे जो प्लांट्स हैं—हायसिंथ और दूसरी तरह के वैजिटेबल प्लांट्स हैं और वेस्ट भी, जो अर्बन या जो रूरल वेस्ट है, गारबेज जिसे कहते हैं, वह भी यह सारा अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा बायो गैस बनाने के लिए । इतना ही नहीं, इसके साथ-साथ मैन्यूर भी उपलब्ध होता है, यानी इसका तिहरा लाभ होता है ।

इससे गांव की गंद हट सकती है जो आजकल देखा जाता है कि गांवों में अक्सर घर का जितना सारा कचरा है, गंद है, गोबर है और भी कुछ है, वह सड़क पर ही डाल दिया जाता है और सड़क ही नाली बन जाती है । तो यह जो गंद है गांव की, वह भी दूर होगी, गैस भी मिलेगी, जो बिलकुल स्मोकलस है, जिसमें फयूल की बिलकुल ही जरूरत नहीं होती और इसके साथ-साथ मैन्यूर भी मिलेगा । तो तीनों तरह का लाभ इस योजना में होता है और वाटर हायसिंथ प्लांटस जो हैं, इसकी एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर बड़े पैमाने पर प्रयोगशालाओं में कार्य हो रहा है और हमारा इरादा है कि इसका ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से उपयोग किया जाए ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : कम्यूनिटी के लिए...

श्री वसंत साठे : यह बड़े पैमाने पर तो कम्यूनिटी के लिए ही है।

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: There is one part of the answer which intrigues me. He says that the target in the Seventh Plan is for 15 lakhs and the present achievement is 1.8 lakhs. But he expresses a doubt. He says, 'if the resources are available'. Is he doubting the formulation of the Plan that the Planning Commission has fixed the target without providing for the resources in the Seventh Plan? That is part (a) of my question. Part (b) of my question is this: what is the cost of the smallest size bio-gas plant? And what is the sibsidy element in that? Is it possible for people having less than four cattlehead to have a gobar gas plant or a bio-gas plant? Is it possible to provide such plants to anybody who is below the top decile in the countryside in terms of Per capita income or per family income? Is it possible to provide bio-gas plants with subsidies to any other persons than belonging to the top decile of income in the countryside? If not, does it not mean that the disparity in the countryside will increase by providing individual bio-gas plants? Part (d) of my question is, is it possible to have under the present circumstance of market economy in the countryside, community gas plants and to what extent has this endeavor to have community biogas plants suceeded and what is the data available with the Minister.

SHRI VASANT SATHE: As far as small and marginal farmers are concerned, in any village or rural area, the best thing is the community gas plant and as I was mentioning just now, this community scheme has succeeded. Many community gas plants have been set up in the country which have proved successful; even near Delhi, there are some such areas ...

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Quantify that 'many'

SHRI VASANT SATHE: I will send the number to you; I do not have the number readily available of the community schemes or community plants in the country.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Can it be counted.

SHRI VASANT SATHE: They can be counted.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Is it in thousands.

SHRI VASANT SATHE: Yes, in thousands, community-wise, not plant-wise.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: You will come up with a correction for the reply.

SHRI VASANT SATHE: If there is a correction will come. So, as I was saying a little while ago, the average size of the plant which is used in homes is about 4 to 6 cubic metre size which costs round-about Rs. 6000 to 7000. The subsidy element varies, depending upon the community like the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, or the region or the area and the lowest is about 33per cent. So, we are trying to encourage the maximum number of people by community centres, as I told you about the integrated community centre scheme, which you want to popularise. There are large number of them as I said, even the small, the marginal and the medium farmers who are coming and you will be surprised to know that majority of them are from the weaker section who are setting up these plants because of subsidy element.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Do you know how many cattle would be required to have a plant of 4 to 6 cubic metre? And a small or a marginal farmer would not have those cattle.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You allow him to answer; don't keep on interrupting.

SHRI VASANT SATHE: It is not only the gobar of the cattle; it is all other garbage, hyacinth and even human excreta, all this can be used. Now the plant is taken according to that size...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सारा गोबर में है या दूसरी व्यवस्था भी है...

श्री वसंत साठे : सारा गोबर में । नाम उसका गोबर गैस रखा, लेकिन है वह बायोगैस ।

It will definitely be useful to the people. But I agree that the largest number of people—every household—can be best served lay community plant and that is the objective ultimately. The question of cost and the question of numbers had come and the hon. Member had asked for figures. As I said, we had thought of 15 lakhs but the number was brought down to 5.5 lakh with an investment in the Seventh Plan of Rs. 177 crores. For 15 lakhs the cost would have been Rs. 500 crores. Now where are we to find this money? If we can find this money from any source including the Finance Minister, I would be very happy.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मंत्री जी, बायोगैस और गोबर गैस में कुछ अन्तर समझ लीजिए, तो जवाब अच्छा रहेगा । मैं इस बात की जानकारी आपसे चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष चला गया और भारतवर्ष की महिलाओं ने उसका लाभ लिया । लेकिन मैंने उस समय भी सरकार को लिखा था कि भारत की महिलाओं को अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो गोबर गैस प्लान्ट हर घर में, हर परिवार में दीजिए । एक बात जो अभी भी उसके साथ अटैच नहीं है वह यह है कि गोबर गैस प्लान्ट्स के साथ शौचालय, लैट्रिन नहीं है । अगर आप गोबर गैस के साथ इसका प्रचार करके महिलाओं के शौचालय इसमें अटैच करा दें तो गोबर गैस की युटिलिटी तो बढ़ेगी ही साथ ही साथ आज भारत में सबसे दुखद स्थिति महिलाओं के लिए शौचालयों में जाने की है । लेकिन शौचालयों के लिए सब्सिडी आप नहीं दे रहे हैं । अगर आप सचमुच में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भारत की ग्रामीण महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज यह होगी कि शौचालय को अनिवार्य रूप से गोबर गैस प्लान्ट के साथ जुड़वायें । अगर आप ऐसा करेंगे तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी । दूसरा मेरा सवाल है कि . . .

उपसभापति : एक ही सवाल का जवाब आने दीजिए ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : गोबर गैस प्लांट सचमुच में आज ग्रामीणों के लिए एक अभूतपूर्व चीज है। इन्होंने रिसोर्सेज की

बात कही इसलिए मैं कह रहा हूं कि गोबर गैस प्लान्ट एक पंथ तीन काज हैं, जो आपने भी अभी स्वीकार किया है । इसमें एक तो गोबर जो बेकार जल कर राख हो जाती है या इसमें यूज हो जाती है तो वह जलावन का काम भी देता है और बचा हुआ पदार्थ रेडी मैड खाद का काम देता है । आपके जितने भी कैमिकल . . .

श्री उपसभापति : आप समझाइये नहीं, सवाल करिये ।

श्री जगदंबी प्रसाद यादव : रिसोर्सेज बता देता हूं ।

गोबर गैस प्लान्ट इतने रिसोर्सेज दे सकता है कि इससे हजारों करोड़ों रुपये की आपकी जो कैमिकल फर्टिलाइजर है, उसकी बचत की जा सकती है इसलिये उसको भी हिसाब करके देख लें और मैं चाहता हूं कि आपके हिसाब से पौने छः लाख गांव क्या 5.5 लाख में भी एक गोबर गैस प्लान्ट नहीं दे सकेंगे । इसलिये आपका 15 लाख भी जो है वह कम है अगर आप ग्रामीणों के बारे में कोई योजना साथ ले सकते हैं । इसलिये मेरा एक निवेदन यह भी होगा, इस प्रश्न के साथ कि आप 5 लाख से 30 लाख पर जाइये लेकिन 15 लाख से 5 लाख पर न आइये और रिसोर्सेज (**व्यवधान**)

श्री बसंत साठे : मैं सदस्य को बहुत धन्यबाद देता हूं, उन्होंने सवाल भी पूछा और उसका जवाब भी दे दिया है । वे संतुष्ट होंगे, ऐसी आशा है ।

Import of technology by IDPL

*387. SHRIMATI MAIMOONA SULTAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstarred Questions 171 and 963 given in the Rajya Sabha on the 18th November and 25th November, 1985 and state:

(a) names of the drugs for which technologies were found obsolete by IDPL;

(b) whether it is a fact that the payment is made in respect of imported technologies after satisfaction of the process, yield, economics, production on commercial scale;

(c) if so, what are the basis of arriving at the conclusion of obsolete technology later on;

(d) names of drugs for which payments for technical know how were made; and

(e) who gave the certificate of satisfaction and whether any action was taken on this account?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS (SHRI R. K. JAICHANDERA SINGH): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) According to Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL) there is need for technology upgradation in respect to many products such as Penicillin, Streptomycin, Erthromycin and Griseofulvin.

(b) Know-how fees for imported technology was required to be paid in instalments. The last instalment was required to be made after satisfactory performance of trial within the time stipulated in the agreement.

(c) Does not arise.

(d) These details have been furnished in Rajya Sabha Unstarred Question No. 171 answered on 18th November, 1985 referred to by the Hon'ble Member.

(e) The Certification of satisfactory conclusion of trial runs was done on the bassis of plant level committees, comprising the General Manager, Works Manager, Chief Technologist and Chief of R&D.

SHRIMATI MAIMOONA SULTAN: Madam in regard to the question, I would first, like to point out one or two relevant portions from the statement and then to proceed to my main question. In the statement, in (b), it has been said 'know-how fees for imported technology